सीएजी रिपोर्ट मामले पर विभाग ने स्पष्ट किया रुख

सवा करोड़ परिवारों को दिए गए जॉब कार्ड

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

ग्रामीण विकास विभाग ने सीएजी द्वारा मनरेगा योजना में उठाई गई आपत्तियों पर अपना पक्ष रखा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2007-12 के लिए मनरेगा का ऑडिट किया है। इस मामले में विभाग का कहना है कि 2007-12 के दौरान राज्य में 1 करोड़ 33 लाख 81 हजार 535 परिवारों को जॉब कार्ड दिए गए हैं। इस दौरान औसतन प्रतिवर्ष 38 लाख 51 हजार 921 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराए गए। इस दौरान कुल 5433 मानव दिवसों का सृजन किया गया है। प्रतिवर्ष औसतन 28 मानव दिवस प्रति परिवार की दर से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

राज्य में कार्य की मांग के 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। सिर्फ अररिया जिले की एक पंचायत में समय पर काम उपलब्ध नहीं कराए जाने से 613 परिवारों को 11.27 लाख बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। 2007-12 के दौरान 8525 करोड़ रुपए उपलब्ध हुए, जिसमें 8488 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस दौरान चार लाख 44 हजार 536 काम लिए गए, जिसमें 3 लाख 5 हजार 783 काम पूरा हो गए। 1 लाख 38 हजार 753 काम निर्माणाधीन हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन में खुलापन और पारदर्शिता लाने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। महिलाओं की भागीदारी 34 प्रतिशत हो गई है।

विभाग ने यह माना है कि शुरुआत में वार्षिक कार्य योजना बनाने में विलंब हुआ था। 2010 से सभी पंचायतों में 2 अक्टूबर को ग्रामसभा होती है और समय सीमा के अंदर कार्य योजना तैयार होती है। पंजीकृत परिवारों की संख्या बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने से किसी को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भुगतान कार्य के आधार पर होता है। एक परिवार को एक से अधिक जॉब कार्ड निर्गत करने से भी कोई फायदा नहीं होता। कार्य भौतिक उपस्थिति के आधार पर मिलता है। विभाग ने डुप्लीकेट कार्ड की व्यापक छानबीन करायी है। इस वर्ष 14 लाख से अधिक डुप्लीकेट कार्ड को निरस्त किया गया है। श्रम बजट शुरू के वर्षों में समय पर तैयार नहीं हुए, लेकिन अब व्यापक सुधार हो गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में राशि मिलने से राशि खर्च नहीं हो पाती है।

लाभुकों को इस वर्ष से फोटो जॉब कार्ड जारी किया जा रहा है। मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से हो रहा है। शिकायतों के निपटारे के लिए सशक्त व्यवस्था की गई है। 11 जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। शेष जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।